(ग) क्या धनराशि के वसूल करने में कोई विलम्ब हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) जी, हा ।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी के आधार पर निर्माताओं को आबंटित वाणिज्यिक प्लाटों के सम्बन्ध में शेष प्रीमियम के भुगतान के लिए उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण से समयवृद्धि के लिए कहा । नीलामी की शर्तों के अनुसार नीलामी की तारीख को नीलामी की समाप्ति पर 25 प्रतिशत बोली की राशि जमा करानी थी जो कि इन सभी मामलों में अदा कर दी गई थी । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नीलामी के नोटिस में यथा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत शेष राशि का भुगतान करना अपेक्षित था । पार्टियों के बाजार में आम मन्दी सहित विभिन्न आधारों पर शेष प्रीमियम के भुगतान के लिए समयवृद्धि देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिये । दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने शेष राशि की वसूली के लिए संशोधित शर्तों के उनके प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए सरकार से कहा । इन शर्तों का अनुमोदन किया गया और पार्टियों द्वारा न्यायालय में दायर मामलों को वापस लेने की शर्त पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चार निर्माताओं के मामलों में संशोधित शर्तों के आधार पर वसूली अनुमेय की थी ।

Review of Workers' Education

1606. SHRI KAPIL VERMA:
SHRI R. SAMBASIVA RAO:
SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY:
SHRI S. W. DHABE:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government propose to undertake a review of the entire scheme of workers' education in the context of emphasis on productivity and induction of new technology; and

(b) if so, what are the proposed changes and improvements which are under Government's consideration?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) and (b) So far the Workers' Education programme was being implemented in the organised sector, mainly in the urban areas. In view of several developments which have taken place in the country, specially the call by the Prime Minister to closely relate productivity with education, science and technology and also keeping in view the stress being laid by the Planning Commission during the Seventh Five Year Plan on organisation of the rural poor, it was decided to review the entire field of workers' education. Accordingly, a general review of the programmes of workers' education was undertaken in a seminar organised on 9—11 July, 1985. The main themes of the seminar were:

(i) Reorganisation and strengthening of the Central Board for Workers Education and financing of Workers' Education Programme.

(ii) Role of trade unions, employers, voluntary agencies and education institutions in Workers' Education Programme—measures and procedures needed for their optimum participation;

(iii) Workers' Education Programmes in the rural unorganised sector, including active association of the Coal Mines and other Welfare Funds in Workers' Education Programme;

(iv) Review and reorganisation of Workers' Education Programme in the organised sector—content, methods, institutional and legal structures.

The recommendations of the Seminar are still awaited.